dependants of the deceased passengers.

There being no casualty in the Yard accident at Patel Nagar Railway Stastation, the question of payment of compensation does not arise.

(d) and (e) The cause of the derailment of Howrah-Delhi-Kalka Mail is under investigation by the Commissioner of Raillway Safety.

As per the findings of the departmental inquiry committee, the derailment of the goods trains at Patel Nagar railway station was due to failure of railway staff.

(f) The loss to railway property has been estimated as under:—

Derailment of Howrah-Delhi-Kalka Mail — Rs. 65.21 lakhs

Derailment of Goods train at Patel Nagar Railway station — Rs. 49,000/-

(g) Some of the important steps taken to control accidents and ensure railway safety are:—

(i) Induction of technical devices to aid the human element.

(ii) Improvement in quality of out-turn from the workshops.

(iii) Intensive and frequent inspections of sensitive installations.

(iv) Monitoring the performance of the staff of critical safety categories such as drivers, guards, station masters, etc.

(v) Intensive training including psychological checks of staff in operational categories.

(vi) Surprise checks against carriage of inflammable/explosive material in passanger trains.

(vii) Provisions of whistle board/ speed breakers and raod signs at the approaches of unmanned level crossings and improving visibility for road users and train drivers.

जवाहर रोजगार योजना समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का धीमा कार्यान्वयन

1219. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22-12-1990 के "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" में "टार्डी इम्पलीमेन्टेशन आफ जे० आर० वाई०, आई० आर० डी० पी०" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जवाहर रोजगार योजना और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आबंटित धनराशि का अनेक राज्य सरकारों द्वारा पूरा-पूरा उपयोग करके समुचित विकास नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां आबंटित धनराशि का 50 प्रतिशत से कम ग्रामीण विकास पर खर्च किया गया है ; और

(घ) क्या शेष धनराशि इन राज्य सरकारों द्वारा अन्य प्रयोजनों के लिए व्यय की गई है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राज्यों में विशेष परिस्थितियों जैसे भारी वर्षा आदि के कारण 1990 तक इन राज्यों में लक्ष्यों के मुकाबले प्रगति धीमी रही है ।

कुछ राज्यों के संबंध में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भी नवम्बर, 1990 तक प्रगति उत्साहजनक नहीं

रही है । यह बात दिसंबर 1990 के अंतिम सप्ताह में हुए राज्यों के सचिवों के सम्मेलन में उनके ध्यान में लाई गई थी । उप-प्रधान मंत्री ने भी संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों के इस्तेमाल में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए लिखा था । इसके फलस्वरूप, इन राज्यों में निधियों का इस्तेमाल किए जाने की गति में सुधार हुआ है । तथापि, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि निधियों का उचित इस्तेमाल नहीं किया गया है ।

(ग) चालू वर्ष की तीसरी तिमाही (अर्थात् दिसंबर, 90) तक जवाहर रोजगार योजना के तहत केवल एक राज्य और तीन केन्द्र शासित क्षेत्रों अर्थात् पंजाब, अंडमान और निकोबार, द्वीप समूह, दमन व दीव तथा दिल्ली में उनको रिलीज की गई निधियों की 50% से कम राशि खर्च की गई थी तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में केवल तीन राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा में 50% से कम राशि खर्च की थी ।

(घ) जी नहीं ।

Supply and price position of edible oil

1220. **SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:** Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to to state:

(a) what is the percentage of comparative rise in the prices of edible oils from the beginning of 1990 till the end of the year and how does it compare with the corresponding period of 1989;

(b) what is the percentage of deficiency in the availability of edible oils both in the open market and through PDS at the end of 1990;

(c) what is the shortfall in the domestic production of oilseeds at the end of 1990 as against the projection and what is the estimated production during 1991; and

(d) the likely supply position vis-a-vis prices of edible oils during 1991 and the steps taken by Government to augment the supply of edible oils and also to contain the prices during 1991?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI RAO BIRENDRA SINGH): (a) The wholesale price index (WPI) of Sub-Group of edible oils exhibited a rise of 31.7 per cent over the year ending December, 1990 and a rise of 3.1 per cent over the corresponding period ending 1989.

(b) Deficiency in the availability of edible oils in the oil year 1990-91 is estimated at around one million tonnes. Precise percentage of deficiency in the availability of the oil in the open market and through PDS is not available.

(c) The targets and estimated production of oilseeds in 1989-90 and 1990-91 are as under:

(In Lakh MT)

Year (Nov.-Oct.)	Target	Production (Estimated)
1989-90 . . .	165.8	167.3
1990-91 . . .	180.0	156.0 163.0

(d) The supply position of edible oils in 1990-91 is estimated to be not more than 48.68 lakh M.T.

Some of the steps taken by the Government to bring down the prices include granting of excise rebate on use of non-conventional oils in the vanaspati, reduction of stock limits of edible oilseeds and oils by dealers/ processors, and manufacturers of edible oils, permitting blending of conventional edible oils with non-conventional oils, distribution of edible